विश्व बैंक

समाचार रिलीज़ सं. 2006/एसएआर

संपर्क-सूत्र:
नई दिल्ली में:
सुदीप मजूमदार
(91 11) 2461-7241
ई-मेल: *smozumder@worldbank.org*
वाशिंगटन में:
एरिक नोरा
(202) 458-4735
ई-मेल: *enora@worldbank.org*

विश्व बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश में जल-संभर विकास के लिए 6 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता

परियोजना समेकित जल-संभर विकास परियोजना के सफल अनुभवों के आधार पर क्रियान्वित की जाएगी

वाशिंगटन, 13 दिसम्बर, 2005: आज यहां विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश मध्यवर्ती-हिमालय जल-संभर विकास परियोजना के लिए 6 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण को स्वीकृति प्रदान की। अपने प्राकृतिक संसाधनों के आधार को विकृत होने से रोकना, प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादक संभावनाओं में सुधार करना तथा ग्रामीण आमदनी बढ़ाने में हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद करना इस परियोजना का उद्देश्य है।

पर्यटन और पन-बिजली के बढ़ते हुए महत्त्व के बावजूद, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था अधिकतर कृषि पर ही निर्भर है। दस परिवारों में से नौ ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से अधिकांश दूरदराज़ घाटियों में स्थित छोटी-छोटी बस्तियों में रहते हैं। राज्य के 60 लाख निवासियों का लगभग 28 प्रतिशत निर्धनता की रेखा से नीचे अपनी गुज़र-बसर करता है। भूमि के ऊंचा-नीचा होने के साथ-साथ सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं तक समुचित पहुंच का अभाव ग्रामीण विकास के मार्ग की रुकावटों में से हैं।

भारत में विश्व बैंक के कंट्री डाइरेक्टर, माइकेल कार्टर, ने कहा, *''हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक विरासत को बरक़रार रखते हुए अपने ग्रामीण इलाकों की उत्पादकता बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता लगातार प्रदर्शित करता रहा है। इस परियोजना से जल-संभरों के प्रबंध में सुधार लाने के लिए नीति के साथ-साथ संस्थागत विकास को समर्थन मिलेगा और साथ ही राज्य में निर्धनों की आजीविका के अवसरों में वृद्धि होगी।''*

वे चार घटक, जिन पर यह परियोजना आधारित है, इस प्रकार हैं:-

- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** जल-संभरों का भागीदारी, खुलेपन और मांग के आधार पर कारगर ढंग से विकास करने के लिए समुदायों और स्थानीय सरकारों की क्षमता का गठन।

- **जल-संभर विकास और प्रबंध:** मृदा और जल-संरक्षण, ग़ैर-कृषियोग्य भूमि के उपचार, फ़सलों और पशुधन-उत्पादन तथा ग्रामीण अंतर्संरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

- **पर्वतीय आजीविका का संवर्द्धन:** विशेष रूप से आदिवासी और कमज़ोर समूहों के लिए कृषि में मूल्य-संवर्द्धन के साथ-साथ आमदनी बढ़ाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा।

- **परियोजना समन्वयन:** परियोजना के विकेन्द्रीकृत ढांचे को समर्थन।

यह परियोजना समेकित जल-संभर विकास परियोजना *(इंटेग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट - आईडब्ल्यूडीपी)* के सफल अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है, जो 30 सितंबर, 2005 को पूरी हो चुकी है।

विश्व बैंक के वरिष्ठ कृषि-अर्थविद्, डैनियल सेलेन ने कहा है, *''इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में समुदायों और इनके स्थानीय निकायों दोनों की भागीदारी से* आईडब्ल्यूडीपी *के अनुभवों से लाभ उठाना है। हमें आशा है कि इस परियोजना के अंतर्गत पर्यावरण में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण निर्धनों की आय में भी वृद्धि होगी।''*

आईडब्ल्यूपी द्वारा किए गए एक आर्थिक विश्लेषण से पता चला है कि इस परियोजना से 1,52,161 हैक्टेयर कृषि-योग्य भूमि और 1,19,867 ग़ैर-कृषियोग्य भूमि को जल-संभर सुरक्षा मुहैया कराई गई और इसका विकास किया गया। जल-संरक्षण संरचनाओं के जरिए परियोजना के क्षेत्र में 13,489 हेक्टेयर इलाके में पूरक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा, जल-संभर सुरक्षा-संबंधी कार्यों से 26,073 हेक्टेयर भूमि को कटाव की चपेट से बचाया गया तथा 7,265 हेक्टेयर भूमि को पुन: उत्पादन-योग्य बनाया गया।

विश्व बैंक की *कन्सेशनरी* संस्था *इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए)* से मिलने वाले इस ऋण का भुगतान चालीस वर्षों में करना होगा। इस ऋण पर, जिसका भुगतान 10 वर्ष बाद शुरू होगा, 0.75 प्रतिशत सर्विस चार्ज देय होगा।

#####

भारत में विश्व बैंक की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए http://www.worldbank.org/in वेबसाइट देखें।

परियोजना संबंधी जानकारी के लिए निम्न वेबसाइट देखें:
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=64290415&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P093720